23) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है? मूल्यांकन आदेश, जिसकी एक प्रति अनुबंध P.4 और मांग नोटिस के रूप में निर्मित की गई है, जिसकी एक प्रति एनेक्स्योर P.5 पर है, उसी दिन और उसी अधिकारी द्वारा पारित किया गया है। यह केवल इन दो आदेशों के पारित होने पर है कि मूल्यांकन पूरा हो गया था और मांग की गई थी। परिणामस्वरूप उदय मिस्टना/रांची क्लब के मामलों में निर्धारित परीक्षण वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट है। यह उल्लेख के योग्य है कि आदेश वर्ष 1994-1995 के मूल्यांकन से संबंधित हैं। अप्रैल, 1998 में पूछताछ के बाद याचिकाकर्ता द्वारा संशोधित रिटर्न दायर किया गया था। याचिकाकर्ता को पता था कि नियत कर के भुगतान में देरी हुई थी। राशि स्पष्ट रूप से धारा 234-बी के तहत देय है। याचिकाकर्ता को कानून के तहत अपनी देयता के बारे में पता था। ब्याज के कारण होने वाली राशि स्वयं मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई थी। इसे याचिकाकर्ता को जाना जाता था। इस प्रकार, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं थी।

(२४) हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, राजस्व की ओर से उठाए गए वैकल्पिक उपाय के सवाल में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है।

(२५) कोई अन्य बिंदु नहीं उठाया गया था।

(२६) परिणामस्वरूप, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है। यह, परिणामस्वरूप, खारिज कर दिया गया है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों में, हम लागत के अनुसार कोई आदेश नहीं देते हैं।

आर.एन.आर.

विजय सोमनी वी. कैप्टन अजय सिंह **505**

(जे.एस. खीर, जे।)

जे.एस. खहर, जे विजय सोमानी, -पुटिशनर

बनाम

कैप्टन। अजय सिंह, -सोन

E.p.no. 2000 का 8।

20 अगस्त, 2001,

लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-एसएस। 80, 81, 83, 86 (5), 100 और 123-कोड ऑफ सिविल प्रक्रिया, 1908-O। Vi rls। 15 और 16, O.VII RI। चुनाव नियमों के 11-आचरण, 1961-फॉर्म 25-चुनाव याचिका- भ्रष्ट अभ्यास के आयोग के आधार पर चुनौती-
याचिका और हलफनामे के सत्यापन में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है-याचिका की स्थिरता के लिए घातक नहीं होने के कारण इस तरह की कमियों को घातक नहीं किया जा सकता है। एस **81 (3)** के जनादेश का नोटरी/शपथ आयुक्त-गैर-अनुपालन-प्रतिवादी को याचिका की एक सच्ची प्रति की गैर-आपूर्ति**, s.86 (1)** के संदर्भ में एक लाइलाज दोष-होने के लिए उत्तरदायी खारिज कर दिया।

यह मानते हुए कि चुनाव याचिका में पूर्ण विवरणों के कथन में कमियां हैं**,** जहां तक पैरा **6 (**ए) में निहित औसत का संबंध है। इसी तरह की कमियां पैराग्राफ **6 (**बी) से (एफ) में किए गए औसत में भी मौजूद हैं। **1951** अधिनियम की धारा **86** की उप-खंड (**5)** के जनादेश के लिए और साथ ही शीर्ष अदालत द्वारा प्रस्तुत विभिन्न निर्णयों को अनबिगोस्ली ने व्यक्त किया कि एक चुनावी याचिका को भौतिक विवरणों में कमी के कारण दहलीज पर खारिज नहीं किया जा सकता है और याचिकाकर्ता को होना चाहिए कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए।

(पैरा १४ और १६)

फर्थर ने कहा, कि चुनाव याचिका के पैरा 6 (ए) में औसत के सत्यापन की एक करीबी परीक्षा से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है कि उसने अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर या सूचना के आधार पर तथ्यों को सत्यापित किया है या नहीं। प्राप्त हुआ। चुनाव याचिका में सत्यापन भी सिविल प्रक्रिया संहिता के VI नियम 15 को ऑर्डर करने के अनुरूप नहीं है। इसी तरह, शपथ पत्र में जो कुछ भी व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर सत्यापित किया गया है, उसे प्राप्त जानकारी के आधार पर भी सत्यापित किया गया है। हलफनामा गजानन कृष्णंजी बापत और एक अन्य वी। दत्तजी रबोबाजी मेघे और अन्य, (1995) 5 एससीसी 347 के फैसले में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यह 1961 के नियमों के लिए 25 के रूप में पुष्टि नहीं करता है। इसलिए, चुनाव याचिका का सत्यापन और वहां जुड़े हलफनामे क्रम में नहीं हैं। हालांकि, मुझे प्रतिवादी के दावे में कोई पदार्थ नहीं लगता है कि याचिका इस आधार पर एकमुश्त बर्खास्तगी के योग्य है।

(पारस 22, 24 और 25)

इसके अलावा, कि हलफनामे के साथ प्रतिवादी से सुसज्जित चुनाव याचिका की ज़ेरॉक्स कॉपी का एक प्रभाव नोटरी द्वारा सत्यापन की कुल अनुपस्थिति का खुलासा करता है। यह ज़ेरॉक्स कॉपी से स्पष्ट है

कि चुनावी याचिका की प्रतिलिपि पर कोई संकेत नहीं है, कि शपथ पत्र ने शपथकर्ता द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण की थी या शपथ आयुक्त ने हलफनामे को देखा था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी को 1951 अधिनियम की धारा 81 (3) के संदर्भ में चुनावी याचिका की 'सच्ची प्रतिलिपि' से सुसज्जित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के लिए एक चुनावी याचिका को खारिज करना अनिवार्य है जो 1951 अधिनियम की धारा 86 (1) के जनादेश के तहत 1951 अधिनियम की धारा 81 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। त्वरित चुनाव याचिका, तदनुसार, खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

(पैरा २ ९)

सत्य पाल जैन, सीनियर विजय कुमार चौधरी के साथ अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए धरज अधिवक्ता।

हरभगवान सिंह, सीनियर एडवोकेट के साथ जे.एस. यादव और अरुण वालिया, प्रतिवादी की वकालत करते हैं।

प्रलय

(1) याचिकाकर्ता रेवारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होने के नाते आम चुनावों में उक्त निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव का चुनाव किया गया था, जिसके लिए 22 फरवरी, 2000 को मतदान आयोजित किया गया था। अजय सिंह, यहाँ प्रतिवादी, को उनके उच्चतम वोटों को अलग करने के कारण चुना गया था। याचिकाकर्ता विजय सोमानी ने 21,112 वोटों को मतदान किया यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या वोट। प्रतिवादी के चुनाव से असंतुष्ट होने के कारण, याचिकाकर्ता ने धारा 80, 81 के तहत तत्काल चुनावी याचिका दायर की, जो कि कैप्टन अजय सिंह के चुनाव को अलग करने के लिए पीपुल्स एक्ट, 1951 के प्रतिनिधित्व की धारा 100 और 123 के साथ पढ़ी। हरियाणा विधान सभा के लिए रेवारी विधानसभा क्षेत्र।

(२) लिखित बयान और प्रतिकृति दाखिल करने के परिणामस्वरूप, १५ नवंबर, २००० को इस अदालत ने निम्नलिखित चार प्रारंभिक मुद्दों को फंसाया:-

(1) क्या चुनाव याचिका को भौतिक तथ्यों का अभाव और प्रारंभिक आपत्तियों को देखते हुए अस्वीकार करना चाहिए ? ओपीआर

(जे.एस. खीर, जे।)

(२) क्या चुनावी याचिका के २ से ६ (ए) से (एफ) परस को सीपीसी के सी/ओ ६ नियम १६ के दलीलों से टकराने के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि कार्रवाई का कोई कारण नहीं बताया गया है और कोई भी मुद्दा नहीं बनाया गया है**?** ओपीआर

(३) क्या चुनाव याचिका कानून के अनुसार ठीक से सत्यापित नहीं है**?** यदि हां**,** तो इसका क्या प्रभाव है**?** ओपीआर

(४) क्या चुनाव याचिका के साथ दायर किया गया हलफनामा दोषपूर्ण है और कानून की नजर में एक हलफनामा नहीं है**?** यदि हां**,** तो इसका क्या प्रभाव है**?** ओपीआर

(३) सी.एम. **2001** के नंबर **5-**ई को एक अतिरिक्त प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करने के लिए प्रतिवादी की ओर से दायर किया गया था। पूर्वोक्त सी.एम. **17** मई**, 2001** को अनुमति दी गई थी**,** जहां अंक **5** के तहत फंसाया गया था:-
(५) क्या चुनाव याचिका की एक सच्ची प्रति लौटे हुए उम्मीदवार/प्रतिवादी को नहीं दी गई है**,** और यदि हां**,** तो क्या प्रभाव के साथ**?**

मुद्दे **Nos**। **1** और **2:**
(४) मुद्दों की संख्या १ और २ पर तर्क सामूहिक रूप से संबोधित किए गए थे। तदनुसार इस तथ्य पर एक साथ निपटाया जा रहा है कि पूर्वोक्त दो मुद्दों का विषय समान है।

(५) प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा यह कहा गया है कि चुनाव याचिका के अनुच्छेद ६ के उप-पैराग्राफ (ए) से (ई) की सामग्री अस्पष्ट हैं और भौतिक तथ्यों के साथ-साथ भौतिक विवरणों की कमी है। पूर्वोक्त दावे के आधार पर**,** यह तर्क दिया जाता है कि चुनावी याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VII** नियम **II** के प्रावधानों के तहत शुरुआत में खारिज करने के योग्य है क्योंकि याचिका कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि चुनाव याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है**,** इसलिए त्वरित याचिका का परीक्षण कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसके अतिरिक्त**,** यह प्रस्तुत किया गया है कि चुनाव याचिका के पैराग्राफ **2** से **6 (**ए) से (एफ) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश **VI** नियम **16** के प्रावधान के संदर्भ में दलीलों को बंद करने के लिए उत्तरदायी हैं।

(६) अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कि याचिका भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं करती है, उत्तरदाता के लिए सीखा वकील ने याचिका के पैरा 6 (ए) में किए गए औसत को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया है। संदर्भ की सुविधा के लिए यहां भी इसे निकाला जा रहा है:-

"कि प्रतिवादी ने 17 फरवरी, 2000 को शाम को शाम को शाम 6.30 बजे एक 'नुकद' (कोने) की बैठक के लिए मोहल्ला 'सांघी का बास' का दौरा किया और अपने वोटों की याचना करने के उद्देश्य से इलाके के सभी निवासियों को एकत्र किया। प्रतिवादी द्वारा की गई अपील, 'सांघी का बास' के मतदाताओं/निवासियों ने अपने मोहल्ला संघी का बेस में 1400-1500 फीट की लंबाई में चलने वाली सड़क के एक छोटे से पैच की खराब स्थिति के बारे में शिकायत की। प्रतिवादी ने वहां एकत्र किए गए मतदाताओं को आश्वासन दिया कि यदि वे 22 फरवरी, 2000 को उसे वोट देने का वादा करते हैं, तो वह चुनाव से पहले सड़क को मजबूत कर लेता और इस उद्देश्य के लिए काम तुरंत शुरू हो जाएगा। इस प्रेरित होने पर स्थानीयता के मतदाताओं ने प्रतिवादी को वोट देने के लिए एक आवाज में वादा किया था। यदि अगले दिन प्रस्तावित सीमेंटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। संघी का बास के मतदाताओं के प्रति प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रेरित वादे के अनुपालन में, मोहल्ला संघी का बास में सीमेंटेड रोड के निर्माण के लिए काम शुरू किया गया था। 18 फरवरी, 2000 की शाम। सीमेंटेड रोड का निर्माण देर रात तक पूरा हो गया, अर्थात 20 फरवरी, 2000 को लगभग 1 बजे। यह काम मतदान से तीन दिन पहले ही शुरू किया गया था और दो दिनों के मतदान से पहले पूरा हुआ था। उक्त सड़क के निर्माण का काम प्रतिवादी द्वारा बिलु @ दया नंद एस/ओ श्री राम दयाल, आर/ओ मंडय्या (कालाका), जिला रेवारी नामक एक ठेकेदार के माध्यम से किया गया था। पहले की टारकोल रोड टूट गया था जिसमें कई पॉट-होल थे। नई सड़क का निर्माण द 'सैंघी का बास' मोहल्ला, केवाल बाजार रोड, रेवाड़ी के वोटों की खरीद के लिए किया गया था। पूरा भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया गया था। इस सड़क और सीमेंटेड सड़क के निर्माण को दिखाने वाली तीन तस्वीरें एनेक्सिड हैं और उन्हें एनेक्सर्स पी -1, पी -2 और पी -3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

ये तस्वीरें हरियाणा फोटो स्टूडियो के एक श्री सुधेश सहगल, 20 फरवरी, 2000 को रेवारी द्वारा ली गई थीं। निर्माण कार्य को दूसरों के बीच, एक श्री सुनील कुमार तिवारी को श्री राम पारसद सी/ओ के पुत्र में किया गया था। एस.टी.डी. बूथ, केवाल बाज़ार, रेवारी जिन्होंने 21 फरवरी, 2000 को याचिकाकर्ता को अपने डोर -टू डोर कैनवसिंग के दौरान याचिकाकर्ता को सूचित किया। प्रतिवादी की यह कार्रवाई पीपुल्स के प्रतिनिधित्व की धारा 123 (1) के तहत एक भ्रष्ट अभ्यास के लिए है, 1951। "
याचिका में निम्नलिखित दोषों को पैरा 6 (ए) में प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा इंगित किया गया है:--

(i) याचिकाकर्ता ने मोहल्ला संघी का बास में जगह नहीं बताई है, जहां प्रतिवादी 17 फरवरी, 2000 को आया था। इस ओर से, यह बताया गया है कि मोहल्ला संघी का बास लगभग 5000 लोगों द्वारा बसे एक छोटे से शहर की तरह है। मोहल्ला संघी का बास को 'गैलिस' और 'नुकाद' के स्कोर शामिल करने के लिए कहा गया है। याचिका 'गली' या 'नुकद' का खुलासा नहीं करती है, जिसका संदर्भ पैरा 6 (ए) में किया गया है;
(ii) याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा की गई सटीक अपील नहीं बताई है, और न ही याचिकाकर्ता ने उन शब्दों को व्यक्त किया है जिसमें उत्तरदाता द्वारा सड़क को सीमेंट करने के लिए कथित आश्वासन दिया गया था। जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर प्रतिवादी द्वारा कथित तौर पर किए गए बयान पर ध्यान दिया, जिसमें उसके वादे भी शामिल हैं, का भी खुलासा नहीं किया गया है;
(iii) याचिका उन लोगों के नाम का भी खुलासा नहीं करती है जो 17 फरवरी, 2000 को मोहल्ला संघी का बास में कथित 'नुकद' बैठक में मौजूद थे, जिन्होंने उनके द्वारा दिए गए आश्वासन पर प्रतिवादी परिणाम के लिए वोट देने के लिए स्वीकार किया था;
(iv) याचिका बिलु उर्फ दया नंद नाम के ठेकेदार के विवरणों का भी खुलासा नहीं करती है, जिसके माध्यम से सड़क का कथित निर्माण प्रतिवादी द्वारा किया गया था;

(v) याचिका भी ठेकेदार को प्रतिवादी द्वारा कथित रूप से किए गए भुगतान के समय या स्थान का खुलासा नहीं करती है, और न ही उस व्यक्ति का नाम जिसने भुगतान किया था न कि इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम भी नहीं। यहां तक कि भुगतान के तरीके का भी खुलासा नहीं किया गया है।

याचिका के अनुच्छेद 6 (ए) में निहित तथ्यात्मक कथन में पूर्वोक्त कमी के आधार पर, प्रतिवादी उसमें निहित दलीलों की एकमुश्त अस्वीकृति चाहता है। अब तक शेष पैराग्राफ में किए गए औसत का संबंध है, यह प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा इंगित किया गया है कि उक्त पैराग्राफ में भी यही कमियां होती हैं, और यह कि विसंगतियों का निर्धारण अनुच्छेद 6 में बताया गया है (ए) याचिका याचिका के शेष पैराग्राफ में विसंगतियों को भी निर्धारित करेगी।

(7) जहां तक प्रारंभिक मुद्दे नं १ और २ का संबंध है, इस सवाल का जवाब दिया जाना है कि क्या चुनाव याचिका को कार्रवाई/भौतिक तथ्यों और विवरणों के कारण के गैर-प्रकटीकरण के कारण शुरू में अस्वीकार किया जा सकता है। पीपुल्स एक्ट के प्रतिनिधित्व के तहत, 1951 (इसके बाद '1951 अधिनियम' के रूप में संदर्भित), चुनावों के बारे में विवादों के संबंध में भाग VI प्रावधानों में, चुनावों के बारे में विवादों के संबंध में। भाग VI के अध्याय II में, धारा 80 से 84 के तहत 1951 अधिनियम एक चुनावी याचिका की प्रस्तुति से संबंधित शर्तों को चित्रित करता है। धारा 81 उस आधार पर है जिस पर एक चुनावी याचिका दायर की जा सकती है। यह चुनावी याचिका दायर करने के लिए सीमा की अवधि भी निर्धारित करता है। धारा 82 उन लोगों के विवरण को निर्धारित करती है जिन्हें चुनाव याचिका में उत्तरदाताओं के रूप में रखा जाना चाहिए। धारा 83 को 'याचिका की सामग्री' के रूप में शीर्षक दिया गया है। पूर्वोक्त प्रावधान का शीर्षक स्पष्ट रूप से उद्देश्य और दायरे का खुलासा करता है। धारा 83 को संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुन: पेश किया जा रहा है:-

"83. पेटिटेशन की सामग्री

(१) एक चुनाव याचिका-

(ए) में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होगा, जिस पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है;

(ख) किसी भी भ्रष्ट प्रथा के पूर्ण विवरणों को निर्धारित करेगा, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास और इस तरह के प्रत्येक प्रथा के आयोग की तारीख और स्थान पर आरोप लगाने के लिए पार्टियों के नामों के रूप में संभव के रूप में पूर्ण एक बयान शामिल किया है; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा, 1908 (1908 का 5) याचिका के सत्यापन के लिए:

[बशर्ते कि याचिकाकर्ता किसी भी भ्रष्ट अभ्यास का आरोप लगाता है। याचिका भी इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास और उसके विशेष के आरोप के समर्थन में निर्धारित रूप में एक हलफनामे के साथ होगी।]

(२) याचिका के लिए किसी भी अनुसूची या अनुलग्नक को याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और याचिका के समान ही सत्यापित किया जाएगा।]

धारा 83 के एक अवलोकन से पता चलता है कि चुनावी याचिका को न केवल भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए, बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा कथित किसी भी भ्रष्ट अभ्यास के पूर्ण विवरणों का भी खुलासा करना चाहिए। प्रतिवादी के लिए सीखे हुए वकील को प्रस्तुत करना यह है कि दलीलें दोषपूर्ण हैं क्योंकि वे 1951 अधिनियम की धारा 83 के जनादेश के अनुरूप नहीं हैं, क्योंकि याचिका न तो भ्रष्ट अभ्यास को स्थिर करने वाले भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण को प्रकट करती है और न ही पूर्ण संकेत देती है और न ही पूर्ण संकेत देती है। कथित भ्रष्ट अभ्यास के विवरण।

(8) अपने दावे को पेश करते समय, उत्तरदाता के लिए सीखा वकील ने शीर्ष अदालत के कई निर्णयों पर भरोसा किया है। धार्तिपकर मदन लाल अग्रवाल बनाम श्री राजीव गांधी (1) पर भरोसा करते हुए, उत्तरदाता के लिए सीखा वकील ने इस अदालत का ध्यान उसमें निम्नलिखित टिप्पणियों पर खींचा है:-

"यदि आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं और भ्रष्ट अभ्यास के विवरणों को दलीलों में नहीं बताया गया है, तो चुनाव

(1) AIR 1987 SC 1577

याचिका का परीक्षण कार्रवाई के कारण के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। कानून का जोर मछली पकड़ने और जांच से बचने के लिए है। इसलिए अदालत के लिए एक सख्त तरीके से भ्रष्ट अभ्यास से संबंधित दलीलों की जांच करना आवश्यक है। "

रिलायंस को सामंत एन बालकृष्ण आदि v जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य, पर भी रखा गया है।

, (2) यह दावा करने के लिए कि **1951** अधिनियम की धारा **83** के तहत यह बताना अनिवार्य है**;** सबसे पहले**,** भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण और दूसरा**,** पूर्ण संभव विवरण। इस ओर से**,** निम्नलिखित टिप्पणियों पर प्रतिवादी के लिए प्रतिवादी के लिए वकील सीखा है:--

"... धारा **83** तब प्रदान करता है कि चुनावी याचिका में उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए**,** जिस पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है और आगे यह भी कि उसे किसी भी भ्रष्ट अभ्यास के पूर्ण विवरणों को भी निर्धारित करना होगा**,** जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिसमें पूर्ण एक बयान भी शामिल है। इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास और प्रत्येक ऐसे अभ्यास के आयोग की तारीख और स्थान पर आरोप लगाने वाले पार्टियों के नामों के बारे में संभव है। अनुभाग अनिवार्य है और पहले भौतिक तथ्यों के एक संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता है और फिर पूर्ण संभव विवरणों की आवश्यकता है। "

भौतिक तथ्यों और भौतिक विवरणों के बीच अंतर को व्यक्त करने के लिए रिलायंस को उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया**, (3)** पर भी रखा गया था। यह प्रतिवादी के लिए सीखे गए वकील का मामला है जो न केवल भौतिक तथ्यों को बल्कि भौतिक विवरणों को भी **1951** अधिनियम की धारा **83** के जनादेश के संदर्भ में एक चुनावी याचिका में प्रकट किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त निर्णय में**,** भौतिक तथ्यों और भौतिक विवरणों को अंडर के रूप में परिभाषित किया गया था-

"सभी प्राथमिक तथ्य जो कार्रवाई या उसके बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए एक पार्टी द्वारा परीक्षण में साबित किए जाने चाहिए**,"** भौतिक तथ्य "हैं। भ्रष्ट अभ्यास के आरोप के संदर्भ में"**, "**भौतिक तथ्य" होगा विशेष रूप से भ्रष्ट अभ्यास के अवयवों का गठन करने वाले सभी बुनियादी तथ्य**,** जो याचिकाकर्ता को उस आरोप में सफल होने से पहले प्रमाणित करने के लिए बाध्य है**,** चाहे वह चुनाव-याचिका में**,** एक

विशेष तथ्य भौतिक हो या नहीं, और इस तरह की आवश्यकता है दलील दी गई एक ऐसा प्रश्न है जो चार्ज की प्रकृति पर निर्भर करता है, जमीन पर निर्भर करता है और मामले की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संक्षेप में, उन सभी

---

(2) AIR 1969 SC 1201

(3) AIR 1976 SC 744

तथ्य जो याचिकाकर्ता को कार्रवाई के एक पूर्ण कारण के साथ तैयार करने के लिए आवश्यक हैं, "भौतिक तथ्य" हैं, जिन्हें दिनांकित किया जाना चाहिए और एक एकल भौतिक तथ्य की मात्रा को भी सेक के जनादेश के अव्यवस्थितता के लिए दलील देने में धारा 83 (1) (ए) विफलता है ।
इसी उद्देश्य के लिए, रिलायंस को अजहर हुसैन बनाम राजीव गांधी पर भी रखा गया था, **(4)** यह बताने के लिए कि धारा **83** के जनादेश को भौतिक तथ्यों के साथ -साथ विशेष रूप से प्रकट करने की आवश्यकता थी। यह दावा करने के लिए कि सामग्री तथ्यों और विवरणों का खुलासा त्वरित मामले में याचिका में नहीं किया गया है, उत्तरदाता के लिए सीखा वकील ने पूर्वोक्त निर्णय में खींचे गए निम्नलिखित निष्कर्षों को इंगित किया:--

"इससे पहले कि हम इन आधारों सेरियटिम से निपटते हैं, हम कानून की बसे हुए स्थिति को बहाल करना उचित मानते हैं क्योंकि यह इस न्यायालय के कई फैसलों से उभरता है, जो हमारे सामने इस सवाल के संबंध में उद्धृत किया गया है कि वास्तव में क्या सामग्री है। अभिव्यक्ति 'भौतिक तथ्य और विवरण' जो चुनाव याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा **83 (1)** के आधार पर अपनी याचिका में शामिल करेगा।

(१) भौतिक तथ्य और विवरण क्या हैं**?**

भौतिक तथ्य ऐसे तथ्य हैं जो अगर स्थापित किए गए याचिकाकर्ता को राहत के लिए पूछी गई राहत देंगे। जवाब देने के लिए आवश्यक परीक्षण यह है कि क्या अदालत चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में एक सीधा फैसला दे सकती है, यदि लौटाए गए उम्मीदवार को याचिका में दलील दिए गए तथ्यों के आधार पर चुनावी याचिका का विरोध करने के लिए दिखाई नहीं दिया था।

(२) एक सरकारी नौकर से प्राप्त सहायता से संबंधित कथित भ्रष्ट अभ्यास के संबंध में, निम्नलिखित तथ्य याचिका को कार्रवाई के कारण के साथ तैयार करने के लिए आवश्यक हैं जो लौटे हुए उम्मीदवार से एक उत्तर के लिए कॉल करेंगे और इसलिए उन्हें दलील दी जानी चाहिए।

---

(4) AIR १ ९ 1986६ एससी १२५३

(a) सहायता का तरीका;
(b) सहायता का माप; और
(c) सहायता से संबंधित सभी विभिन्न रूपों।

(३) एक आरोप के संदर्भ में, चुनाव में सरकारी सेवकों की सहायता प्राप्त करने, प्राप्त करने, प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के संबंध में, यह निम्नलिखित को दलीलने के लिए आवश्यक है:
(ए) प्राप्त या खरीदे गए सहायता के प्रकार या रूप;
(ख) किस तरीके से सहायता प्राप्त की गई या खरीद या खरीद या चुनाव द्वारा प्राप्त या खरीदने का प्रयास किया गया- अपने चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवार। [AIR 1972 SC 515]

(४) लौटे हुए उम्मीदवार को बताया जाना चाहिए कि वह किस सहायता की मांग करनी थी, सहायता का प्रकार, सहायता का तरीका, सहायता का समय, वे व्यक्ति जिनसे वास्तविक और विशिष्ट सहायता की खरीद की गई थी [AIR 1972 SC 515]।

(५) चुनाव याचिका में यह भी बताना होगा कि चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया था और जिस तरह से सहायता प्रदान की गई थी। (एयर 1972 एससी 515) (सुप्रा)।

(६) चुनावी याचिकाकर्ता को सहायता के समय, सहायता के तरीके, सहायता के तरीके, जिन व्यक्तियों से सहायता प्राप्त की गई या खरीद की गई, उसी समय और तारीख को, इन सभी को विशेष रूप से निर्धारित करना होगा। (एयर, 1972 एससी 515) (सुप्रा) "

वी। नारानास्वामी वी। सी.पी. पर भरोसा करते हुए। थिरुनवुककारसु, (5), ने प्रतिवादी के लिए वकील सीखा, यह बताते हैं कि पूर्वगामी निर्णयों में वर्णित कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रही है। प्रतिवादी के लिए सीखा वकील ने इस अदालत का ध्यान उस मामले में तथ्यात्मक विवाद के लिए आमंत्रित किया है, जहां पॉन्डिचेरी विधान सभा से राज्यसभा के प्रति प्रतिवादी का 1951 अधिनियम की चुनाव धारा 123 (1) (बी) (बी) और धारा 100 (1) (डी) के भीतर भ्रष्ट प्रथाओं के कारण चुनौती के अधीन था।

पूर्वोक्त मामले में, यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी स्वयं, उनके एजेंटों और अन्य व्यक्तियों ने उनकी सहमति से डीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, पैटाली मक्कल काची, जनाता दाल और एक स्वतंत्र एमएलए से संबंधित एमएलए को लिया था। पॉन्डिचेरी। सभी उक्त विधायकों का मनोरंजन किया गया और चुनाव की तारीख से एक दिन पहले पांडिचेरी में वापस लाया गया। यह आरोप लगाया गया था कि उक्त विधायकों को प्रतिवादी के लिए मतदान के लिए एक इनाम के रूप में मनोरंजन किया गया था। याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि वह उन विधायकों से मिलना चाहता था, जिन्हें प्रतिवादी द्वारा ले जाया गया था, लेकिन उक्त विधायकों को पहले पांडिचेरी में होटल अशोक में रखा गया था और फिर महाबलीपुरम के पांच सितारा होटलों में ले जाया गया था। उत्तरदाता के खिलाफ किए गए पूर्वोक्त आरोपों पर विचार करते हुए, शीर्ष अदालत ने पूर्वोक्त मामले में दलीलों का जिक्र करते हुए, के रूप में देखा:-

"यह उनका मामला नहीं है कि उन्हें किसी भी तरह से इन विधियों में से किसी भी तरह से मिलने से रोका गया था। यह एक भौतिक तथ्य था कि वह ऐसा करने में विफल रहा। होटल अशोक और अन्य स्थानों पर, महाबलीपुरम में विधियों के नाम और होटल के नाम, जो उन्हें वहां ले गए, जिन्होंने उनके बिलों का भुगतान किया और जो उन्हें वापस लाते हैं, उनकी कमी है। अपीलकर्ता यह नहीं दिखाता है कि वह उन सभी से क्यों नहीं मिल सकता है 2 अक्टूबर, 1997 को विधायक एक स्वतंत्र विधायक के अलावा अन्य एम.एल.एस.ए.एस अन्य राजनीतिक दलों जैसे डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, पीएमके और जनता दल के हैं। बल्कि यह माना जा सकता है कि एम.एल.एस.ए.एस ने अपने राजनीतिक संबद्धता के अनुसार मतदान किया। "

पूर्वोक्त तथ्यात्मक दृढ़ संकल्प के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला:

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि चुनावी याचिका में न केवल भौतिक तथ्यों का अभाव था, इसमें भौतिक विवरणों की कमी थी, दोषपूर्ण सत्यापन और दायर किए गए हलफनामे में निर्धारित रूप में नहीं था। इसके अलावा, भ्रष्ट प्रथाओं की सामग्री, जैसा कि अधिनियम की धारा 123 (1) (बी) और 123 (2) में परिभाषित किया गया है, में भी कमी है। यह अपीलकर्ता का भी मामला नहीं है कि कोई भी विधायक जिसे अपीलकर्ता नहीं कर सकता था।

मीट, किसी भी संतुष्टि को प्राप्त किया, जैसा कि परिभाषित किया गया है, चाहे एक मकसद के रूप में या मतदान के लिए या मतदान से परहेज करने के लिए इनाम, या वोट देने या मतदान से परहेज करने के लिए ऐसे किसी भी एमएलए को प्रेरित करने का कोई प्रेरणा या प्रयास था। इसके अलावा यह अपीलकर्ता का मामला नहीं है कि किसी भी विधायक के किसी भी चुनावी अधिकार के मुक्त अभ्यास के साथ किसी भी अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था, जो कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अधिनियम की धारा **79** के खंड (डी) में परिभाषित किया गया है। यदि किसी विशेष एमएलए को वोट देने के लिए प्रेरित किया गया था या किसी विशेष तरीके से मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया था, तो कोई आरोप नहीं है क्योंकि उनका मनोरंजन किया गया था या अन्यथा। आरोप यह है कि अपीलकर्ता स्वयं विधायकों से नहीं मिल सकता था और उनका मानना था कि अगर उन्हें उनसे मिलने का मौका दिया गया है तो उन्होंने उनके पक्ष में और संबद्धता की पार्टी के खिलाफ उनके वोट को प्रभावित किया होगा। इस बात पर कोई आरोप नहीं है कि विधायक को अपने चुनावी अधिकार का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करने से रोका या प्रभावित किया गया था। जैसा कि पहले कहा गया था कि अपीलकर्ता ने यह नहीं दिखाया कि वह **2** अक्टूबर, **1997** को विधायकों से क्यों नहीं मिल सके, जब वे पांडिचेरी में उपलब्ध थे। भौतिक तथ्य यह होना चाहिए कि अपीलकर्ता को उन विधायकों से मिलने से रोका गया था, जो उन्होंने आरोप नहीं लगाया था और जैसे कि उन्हें इतना रोका गया था कि वे भौतिक विवरणों का गठन करेंगे। "

शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर, यह प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा सख्ती से प्रतिष्ठित है कि भौतिक तथ्यों और विवरणों को तत्काल चुनावी याचिका में व्यक्त नहीं किया गया है। इस प्रकार चुनाव याचिका को **1951** अधिनियम की धारा **83** के जनादेश के संदर्भ में दोषपूर्ण माना जाना चाहिए, और इस तरह से तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(9) मुद्दों पर प्रतिवादी के लिए सीखा वकील की प्रस्तुतियाँ के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले, यह दावा किया जाता है कि चुनाव याचिका में कोई कमी नहीं है। इस ओर से, यह प्रस्तुत किया गया है कि चुनावी याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण है और यह भी पूर्ण सामग्री विशेष रूप से निर्धारित करता है। मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रारंभिक मुद्दे

Nos 1 और **2** प्रतिवादी की ओर से उठाए गए हैं। दूसरे, यह औसत है कि निश्चित रूप से भौतिक तथ्यों में कोई कमी नहीं है **I**

और यह कि भले ही भौतिक विवरणों में कोई कमी हो, वही घातक नहीं है। इस दावे को प्रमाणित करने के लिए निर्भरता को मुख्य रूप से **1951** अधिनियम की धारा **86** की उप-धारा (**1**) पर रखा गया है। तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भौतिक विवरणों में कमी है, याचिकाकर्ताओं को उक्त दोषों को ठीक करने की अनुमति दी जा सकती है। उपरोक्त विवाद के आगे, रिलायंस को **1951** अधिनियम की धारा **86** की उप-धारा (**5**) पर रखा गया है, जैसा कि इस ओर से शीर्ष न्यायालय द्वारा घोषित कानून भी है।

(**10**) तर्कों को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ता के लिए वकील सीखा, **1951** अधिनियम की धारा **86** की उप-वर्गों (**1**) और (**5**) पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया। पूर्वोक्त उप-धारा को यहां निकाला जाता है-

"86. चुनाव याचिका का परीक्षण (**1**) उच्च न्यायालय एक चुनावी याचिका को खारिज करेगा जो धारा **81** या धारा **82** या धारा **117** के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।

इस उप -खंड के तहत एक चुनावी याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के स्पष्टीकरण -आदेश को धारा **98** के खंड (ए) के तहत बनाया गया एक आदेश माना जाएगा।

(२)

(३) ***

(४)

(५) उच्च न्यायालय, लागत के रूप में इस तरह की शर्तों पर और अन्यथा जैसा कि यह फिट हो सकता है, याचिका में कथित किसी भी भ्रष्ट अभ्यास के विवरणों को संशोधित करने या इस तरह से प्रवर्धित करने की अनुमति दे सकता है जैसे कि इसकी राय में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है याचिका का एक निष्पक्ष और प्रभावी परीक्षण, लेकिन याचिका के किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं देगा, जिसमें याचिका में पहले कथित रूप से कथित भ्रष्ट अभ्यास के विवरणों को पेश करने का प्रभाव होगा। "

उप-धारा (**1**) के एक परसी से पता चलता है कि एक चुनावी याचिका को खारिज किया जा सकता है यदि यह **1951** अधिनियम की धारा **81, 82** और **117** में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करता है। प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा उन्नत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि यह प्रतिवादी का मामला नहीं है कि चुनाव याचिका **1951** अधिनियम की धारा

81, 82 या **117** के तहत पोस्ट की गई कमियों से ग्रस्त है। मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में,

सीखा वकील यह बताता है कि उत्तरदाता द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियों को मुद्दों के माध्यम से **1** और **2** पूरी तरह से गलत तरीके से किए गए हैं। याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने श्री एच। डी। में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान किए गए फैसले पर निर्भरता रखी है। रेवना वी। श्री जी। पुटास्वामी गौड़ा और ओआरएस।**, (6)** के रूप में:-

महत्वपूर्ण रूप से धारा **86** धारा **83** का उल्लेख नहीं करता है और धारा **83** के गैर-अनुपालन से धारा **86** के तहत बर्खास्तगी नहीं होती है। इस अदालत ने यह निर्धारित किया है कि धारा **83** के गैर-अनुपालन से याचिका को खारिज करने का कारण हो सकता है यदि मामला के भीतर गिरता है तो **O. 6 R. 16** या **0. 7 R. 11 C.P.C** का दायरा।

इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के ध्यान को उप-धारा (**5)** पर आमंत्रित किया गया है, जो स्पष्ट रूप से यह बताता है कि भौतिक विवरणों में कमी के मामले में, अदालत याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता को लागत जैसे शर्तों के अधीन करने की अनुमति दे सकती है। और कथित भ्रष्ट प्रथा के संबंध में पूर्ण सामग्री पार्टिकफुलर्स बताने के लिए, जो पहले याचिका में नहीं सुनाई गई थी। पूर्वोक्त उप-धारा के आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा बताई गई कमियां घातक प्रकृति की नहीं हैं।

(११) जहां तक प्रतिवादी के लिए सीखे गए वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का संबंध है, यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा माना जाता है कि भौतिक तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण एक चुनावी याचिका के लिए घातक होगा। हालांकि, इस ओर से यह तर्क दिया गया है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, रिलायंस को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व अवलोकन पर रखा गया है, जो उधव सिंह बनाम माधव राव स्किंडिया, **(**सुप्रा) में सामग्री के प्रकाशन और भौतिक तथ्यों के बीच के अंतर को व्यक्त करने के लिए है।

"इस प्रकार यह देखा जाएगा कि श्री शिव प्रताप सिंह के खिलाफ धारा **123 (2)** के तहत भ्रष्ट अभ्यास का पूरा आरोप है, सभी" भौतिक तथ्य "याचिका में बताए गए थे। खतरे को प्रशासित करने की अनुमानित तारीख-जो केवल एक सामग्री थी। विशेष रूप से एक भौतिक तथ्य से अलग किया गया था। केवल जगह और खतरे को देने का सटीक समय नहीं बताया गया था। लेकिन ये, सबसे अच्छे, केवल विशेष सामग्री में थे

और "भौतिक तथ्य" नहीं। इस तरह के विवरणों को प्रस्तुत करने का अवसर तभी उत्पन्न होता जब प्रतिवादी ने उनसे पूछा हो। इसी तरह, श्री शिव प्रताप सिंह के पते आदि के आगे और बेहतर विवरण विवरणों की श्रेणी में आते हैं "।

प्रतिवादी द्वारा भरोसा किए गए फैसले के आधार पर, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने चुनाव याचिका के पैरा **6 (**ए) में किए गए औसत (जो ऊपर निकाला गया है) के लिए इस अदालत का ध्यान आकर्षित किया है। याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील, पैरा **6 (**ए) में दलीलों के विश्लेषण पर एक सवाल था, क्या इस अदालत ने चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया होगा, यदि प्रतिवादी चुनावी याचिका का विरोध करने के लिए दिखाई नहीं दिया था**?** याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के अनुसार, पूर्वोक्त परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए एकमात्र परीक्षण है कि क्या भौतिक तथ्यों में कमी है। यदि पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में है, तो यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि भौतिक तथ्यों में कोई कमी नहीं है, और यदि उत्तर सकारात्मक है यानी यदि अदालत ने गैर-उपस्थिति के बावजूद चुनाव याचिका को खारिज कर दिया होगा। लौटे हुए उम्मीदवार, निष्कर्ष जो खींचा जाना चाहिए, वह यह है कि वास्तव में भौतिक तथ्यों के कथन में कमी है।

(१२) अनुच्छेद ६ (ए) में सुनाए गए तथ्यों के एक करीबी अवलोकन पर और पैराग्राफ ६ (बी) से (एफ) में बुद्धिमानों की तरह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि चुनाव याचिका का विरोध नहीं किया गया था, तो यह अदालत, इस अदालत द्वारा विरोध किया गया था। चुनाव याचिका में चुनाव याचिकाकर्ता के पक्ष में एक फैसला दिए गए चुनाव याचिका में उन तथ्यों के आधार पर होगा। अजहर हुसैन के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खींचे गए पैरा-मीटर के आधार पर पूर्वोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर यह माना जाता है कि यह माना जाता है कि भौतिक तथ्यों में कोई कमी नहीं है क्योंकि तत्काल चुनाव याचिका की दलीलें चिंतित हैं। ।

(१३) तत्काल मामले में विश्लेषण करने की तथ्यात्मक स्थिति, इसलिए, यह है कि क्या याचिकाकर्ता ने **1951** अधिनियम की धारा **83 (1) (**बी) के तहत परिकल्पित सभी भौतिक विवरणों का खुलासा किया है। पूर्वोक्त प्रावधान के एक अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को संभव के रूप में पूर्ण एक बयान को निर्धारित करना आवश्यक है। ", उन पार्टियों के नामों के बारे में जो इस तरह के भ्रष्ट प्रथाओं और कथित भ्रष्ट की तारीख और स्थान और स्थान पर आरोप लगाते हैं। अभ्यास। सामग्री तथ्यों का संदर्भ देते हुए **1951** की धारा **83** का जनादेश अधिनियम की आवश्यकता है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों की "संक्षिप्त" बयान होना चाहिए **।**

. "संक्षिप्त" शब्द का अर्थ है छोटा या संक्षिप्त. अब तक जैसा कि सामग्री विवरण संबंधित हैं, 1951 अधिनियम की धारा 83 "पूर्ण" सामग्री विशेष की स्थापना की आवश्यकता है. शब्द "पूर्ण" जब गर्भनिरोधक-भेद में जांच की जाती है कि शब्द "संक्षिप्त" व्यक्त करता है विधायी प्राधिकरण का इरादा, अर्थात् वह सामग्री विशेष बिना किसी अस्पष्टता को छोड़ने के लिए यथासंभव विस्तृत रूप से सेट किया जाना चाहिए भौतिक तथ्यों की सटीक प्रकृति के बारे में.

(1) के लिए सीखा वकील की पहली प्रस्तुति इस ओर से प्रतिवादी यह है कि मोहल्ला संघ का बास जहां प्रतिवादी ने 17 फरवरी, 2000 को एक छोटे शहर की तरह बैठक की लगभग 5000 लोगों का निवास. पूर्वोक्त मोहल्ला में शामिल हैं 'गॉल' और 'नुकैड्स' के स्कोर'. के लिए वादों से यह संभव नहीं है एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जहां कथित बैठक वास्तव में थी आयोजित. उस सटीक स्थान की गैर-आपूर्ति जहां बैठक थी आयोजित सामग्री विशेष में कमी होने का आरोप है. जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1951 अधिनियम की धारा 83 (1) (बी) पोस्ट करती है, *अन्य बातों के साथ,* के आयोग के स्थान के रूप में संभव के रूप में एक बयान पूर्ण इस तरह के भ्रष्ट व्यवहार का खुलासा किया जाना चाहिए. तत्काल चुनाव है याचिका में कथित भ्रष्ट आयोग के स्थान का खुलासा किया गया प्रावधान के जनादेश के संदर्भ में अभ्यास? मेरे विचार में, उत्तर नकारात्मक में है. प्रतिकृति इस तथ्य से इनकार नहीं करती है कि मोहल्ला संघ का बास वास्तव में एक बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है व्यक्तियों की संख्या. बड़ी संख्या के बारे में भी कोई इनकार नहीं है उसमें 'गॉल' और 'नुकल्स' शामिल हैं. ऐसा होने के नाते, निश्चित रूप से एक है उस स्थान के पूर्ण विवरणों के गैर-प्रकटीकरण में कमी जहां कथित बैठक हुई थी।

(2) इस ओर दूसरा विवाद यह है कि पाठ्यक्रम के दौरान मतदाताओं को प्रतिवादी द्वारा की गई सटीक अपील `नुकद 'बैठक का भी खुलासा नहीं किया गया है. याचिकाकर्ता सॉलिसिटिंग के लिए प्रतिवादी द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है सड़क को मजबूत करने के बदले में वोट. चुनाव याचिका न तो मतदाताओं के आश्वासन का खुलासा करता है, न ही अपील का प्रतिवादी. यदि अपील के बयान की सटीक प्रकृति और आश्वासन यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रतिवादी वास्तव में है एक भ्रष्ट अभ्यास किया या नहीं, तो ये तथ्य सामने आएंगे सामग्री विशेष अन्यथा नहीं. मैं उस

विचार का हूं यह अपील की सटीक प्रकृति को निर्धारित करने के लिए बहुत सामग्री है आश्वासन की सटीक प्रकृति. इसलिए अनुपस्थिति में, इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है

कि क्या प्रतिवादी वास्तव में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का दोषी है। ऐसा होने के नाते, मेरे विचार में, प्रतिवादी द्वारा की गई अपील की सटीक प्रकृति के साथ-साथ मतदाताओं द्वारा दिए गए आश्वासन की सटीक प्रकृति का गैर-प्रकटीकरण भौतिक विवरणों में कमी का गठन करता है।

(३) यह और आरोप लगाया गया है कि उन लोगों के विवरण जो 'नुकद' बैठक में मौजूद थे, जहां प्रतिवादी द्वारा अपील की गई थी और मतदाताओं द्वारा आश्वासन दिया गया था और इसका खुलासा किया जाना चाहिए। सामग्री विवरण का प्रकटीकरण। निस्संदेह, अपील और आश्वासन केवल तभी होगा जब मतदाता विशेष चुनावी प्रक्रिया के लिए प्रतिवादी से प्रभावित हो। मतदाताओं की अनुपस्थिति में, न तो अपील, और न ही आश्वासन प्रतापित होगा। चुनाव याचिका ने कहा कि 'नुकद' बैठक के दौरान उपस्थित मतदाताओं के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। मेरे विचार में, उन मतदाताओं के नामों के गैर-प्रकटीकरण के लिए समान राशि का गैर-प्रकटीकरण, जिन्होंने आश्वासन दिया था और जिनके लिए प्रतिवादी ने कथित तौर पर भौतिक विवरणों के गैर-प्रकटीकरण के लिए एक अपील राशि बनाई थी।

(४) यह बताया गया है कि बिलु @ दया नंद के पूर्ण विवरणों का गैर-प्रकटीकरण, जिसके माध्यम से सड़क का कथित निर्माण प्रतिवादी द्वारा किया गया था, भौतिक विवरणों के गैर-प्रकटीकरण के लिए भी मात्रा है। पूर्वोक्त आपत्ति को स्वीकार करना संभव नहीं है। पूर्वोक्त व्यक्ति के पूर्ण विवरणों को पैरा **6** (ए) के रूप में इनस्मुच का खुलासा किया गया है, न केवल उनके पेरेंटेज का खुलासा करता है, बल्कि उनके आवासीय पते का भी खुलासा करता है।

(५) अनुच्छेद ६ (ए) में किए गए औसत के रूप में अंतिम आपत्ति है कि चुनावी याचिका उस समय या स्थान का खुलासा नहीं करती है जब भुगतान कथित रूप से ठेकेदार द्वारा प्रतिवादी द्वारा किया गया था, और न ही उस व्यक्ति का नाम जिसने बनाया था। भुगतान और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जिसने इसे प्राप्त किया। यह निश्चित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों में सबसे अधिक प्रासंगिक है, यह स्थापित करने के लिए कि प्रश्न में सड़क को प्रतिवादी द्वारा सीमेंट किया गया था। प्रतिवादी को यह स्थापित करने के लिए कि प्रतिवादी को सड़क पर सीमांकित करने का एकमात्र आधार यह है कि उन्होंने उस ठेकेदार को भुगतान किया जिसने काम को अंजाम दिया। प्रश्न में। पूर्वोक्त संदर्भ में देखा गया, ठेकेदार को प्रतिवादी द्वारा

कथित रूप से किए गए भुगतान ने विशेष रूप से किसी सामग्री की स्थिति को मान लिया। इस प्रकार ठेकेदार को प्रतिवादी द्वारा कथित भुगतान से संबंधित पूर्ण संभव तथ्य का खुलासा करने के लिए याचिकाकर्ता पर अवलंबी है।

पूर्वोक्त तथ्यों का खुलासा नहीं करने के बाद, याचिकाकर्ता ने, मेरे विचार में फिर से कथित घाव अभ्यास के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं बताने में लड़खड़ाया।

(१४) ऊपर दिए गए निष्कर्षों से, यह स्पष्ट है कि चुनाव याचिका में पूर्ण सामग्री विवरणों के कथन में कमियां हैं, जहां तक पैरा 6 (ए) में निहित औसत का संबंध है। इसी तरह की कमियां पैराग्राफ 6 (बी) से (एफ) में किए गए औसत में भी मौजूद हैं।

(१५) भले ही याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए वकील के अनुसार, भौतिक विवरणों में कमी हो, लेकिन उन्हें उक्त कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कि याचिकाकर्ता को पूर्वोक्त कमियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, याचिकाकर्ता के लिए वकील ने सीखा कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वी.एस. अचुथानंदन वी.पी.जे. फ्रांसिस और अन्र। (7) और उसमें दर्ज निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया:-

"यह इस प्रकार दिखाई देगा, कि चुनावी याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता था क्योंकि सीखा परीक्षण न्यायाधीश के अनुसार भ्रष्ट अभ्यास के बारे में आरोप अस्पष्ट थे और" भौतिक तथ्यों और पूर्ण विवरणों का खुलासा नहीं किया था " "भ्रष्ट प्रथा का आरोप लगाया। यह स्पष्ट है कि सीखा परीक्षण न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में आरोपों के 'भौतिक तथ्यों' और 'भौतिक विवरण' के बीच अंतर नहीं किया। इस बिंदु पर कानून अच्छी तरह से है -सैटल जो कि सीखा ट्रायल जज द्वारा सराहना की गई प्रतीत नहीं हुई है। इस अदालत के विभिन्न उच्चारणों का उल्लेख करने के बाद बालवान सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण और ओआरएस (1960) 3 एससीआर 91), सैमंत एन। बालकृष्णा), जिसमें शामिल हैं। और अन्र। वी। जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य (1969) (3) एससीसी 238), वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनाम। जगजीवान और अन्य (1972) (1), SCC 826), श्री उधव सिंह बनाम माधव राव सिंधिया,

(7) J.T. 1999 (2) SC 347

(1977 (1) SCC 511), F.A. Sapa और अन्य v। सिंगोरा और अन्य शिवरामगौड़ा आदि वी। टी.एम. चंद्रशेखर आदि JT 1998 (8) SC 278 ने कहा कि भौतिक तथ्यों को विनती करने में विफलता चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दायर करने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद इस तरह के भौतिक तथ्यों को पेश करने की याचिका का कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति सामग्री के विवरणों को बाद के चरण में एक उपयुक्त संशोधन द्वारा ठीक किया जा सकता है। "

रिलायंस को फिर से श्री एच.डी. रेवना का मामला (सुप्रा) निम्नलिखित कंसों पर खींचा गया:-

"इस अदालत ने बार -बार 'भौतिक तथ्यों' और 'विवरण' के बीच अंतर को इंगित किया है। अब तक 'भौतिक तथ्यों' का संबंध है, इस अदालत ने यह माना है कि उन्हें चुनावी याचिका में पूरी तरह से निर्धारित किया जाना चाहिए और यदि कोई तथ्य है यह निर्धारित नहीं है, याचिकाकर्ता को बाद में संबंधित साक्ष्य को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है; न ही उसे चुनावी याचिका के लिए निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी। । श्री लक्ष्मी नारायण और अन्य (1960) 3 एस.सी.आर. यह देखा गया कि यदि कोई आपत्ति ली गई थी और ट्रिब्यूनल का विचार था कि विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, तो याचिकाकर्ता को विवरणों में संशोधन या प्रवर्धित करने का अवसर होना चाहिए था और यह केवल गैर-अनुपालन की घटनाओं में था। विवरणों की आपूर्ति करने का आदेश, चार्ज को हटाया जा सकता है। "

ऊपर देखे गए निर्णय के आधार पर सामूहिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि भौतिक विवरणों में कमी है, याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका में संशोधन करने और आगे के तथ्यों की आपूर्ति करने का अवसर दिया जा सकता है। भौतिक विवरणों में कमी। इस ओर से, रिलायंस को रूप लाल साथी बनाम नछत्तर सिंह (8) में दिए गए निर्णय पर भी रखा गया था। अदालत का ध्यान निम्नलिखित टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया गया था:-

"अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (1) के खंड (ए) ने कहा कि एक चुनावी याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होगा, जिस पर चुनाव याचिकाकर्ता निर्भर करता है। यह ए के दावे के बयान का कोई हिस्सा नहीं है। चुनाव याचिकाकर्ता को रक्षा का अनुमान लगाने और यह बताने के लिए कि उसे इसके जवाब में क्या कहना होगा। धारा 83 के उप-धारा (1) के खंड (1) के अंतराल। वह धारा 123 (7) के तहत लौटे उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देता है, जिसमें इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास और इस तरह के प्रत्येक अभ्यास के कमीशन की तारीख और स्थान पर आरोप लगाया गया है। ऑर्डर VI के आधार पर कम, कोड का नियम 4 जो पढ़ता है:

"4. उन सभी मामलों में जिनमें पार्टी की दलील किसी भी गलत बयानी, धोखाधड़ी, विश्वास का उल्लंघन, विलफुल डिफ़ॉल्ट, या अनुचित प्रभाव पर निर्भर करती है, और अन्य सभी मामलों में, जिनमें विशेष रूप से परे आवश्यक हो सकते हैं जैसे (यदि आवश्यक हो तो तारीखों और वस्तुओं के साथ) याचिका में कहा जाएगा। "

उच्च न्यायालय के पास एक चुनावी याचिका की कोशिश करते हुए पर्याप्त शक्ति है, जो आगे और बेहतर विवरण के रूप में दावे की प्रकृति के रूप में निर्देशित है, जो कि आदेश VI के तहत, नियम 5 के नियम के तहत है, जो पढ़ता है:

"5. दावे या रक्षा की प्रकृति का एक और बेहतर बयान, या किसी भी मामला के आगे और बेहतर विवरण

8)	AIR	1982	SC	1559

किसी भी याचिका में कहा गया मामला सभी मामलों में इस तरह की शर्तों पर आदेश दिया जा सकता है, जैसे कि लागत और अन्यथा, जैसा कि बस हो सकता है। "

इसलिए, मौजूदा कानूनी स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि न केवल 1951 अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा 5 पर आधारित है, बल्कि ऊपर उल्लिखित शीर्ष न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों के आधार पर भी है कि सामग्री विशेष में कमी हो सकती है सुधारा गया। दूसरे शब्दों में कहा गया है, एक चुनावी याचिका को केवल इस तथ्य के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में पूरी तरह से भौतिक विवरणों का खुलासा नहीं किया है।

(१६) निस्संदेह, १ ९ ५१ अधिनियम की धारा of६ की उप-धारा (५) के जनादेश के साथ-साथ याचिकाकर्ता के लिए सीखे गए वकील द्वारा विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया था। भौतिक विवरणों में कमी के कारण और याचिकाकर्ता को कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए, तदनुसार, मुद्दों को निर्धारित करते हुए, 1 और 2, यह आयोजित किया जाना चाहिए कि तत्काल याचिका को इस स्तर पर कमियों के लिए खारिज नहीं किया जा सकता है ।

मुद्दे न. 3 और 4:

(17) इन मुद्दों पर सामान्य तर्कों को संबोधित किया गया था। वे तदनुसार एक साथ निपटाया जा रहा है। जहां तक अंक नंबर 3 का संबंध है, यह प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा किया जाता है कि चुनाव याचिका पर सत्यापन दोषपूर्ण है और जैसे कि चुनावी याचिका को खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि पैरा 6 (ए) का सत्यापन सत्यापन के कानून के खिलाफ है, क्योंकि दलीलों को ज्ञान द्वारा भी दोनों को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सत्यापन या तो व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर या प्राप्त जानकारी के आधार पर होना चाहिए। इस तथ्य के कारण कि याचिका में किए गए औसत के सत्यापन को

ज्ञान के साथ -साथ जानकारी पर भी बनाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वही अनुचित है। चूंकि दलीलों को ठीक से सत्यापित नहीं किया गया है, इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि तात्कालिक याचिका को उचित रूप में नहीं कहा जा सकता है और इस तरह, खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदाता के लिए सीखा वकील आगे बताते हैं कि रिट याचिका के अन्य पैराग्राफ का सत्यापन उसी कारण से समान रूप से दोषपूर्ण है।

(18) यह नोटिस करने के लिए सामग्री होगी कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा बनाम जगजीवान और अन्य में सुप्रीम कोर्ट, **(9)** चुनाव याचिका के सत्यापन और शपथ पत्र के सत्यापन के सत्यापन के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए।

".... अधिनियम की धारा **83** में कहा गया है कि एक चुनावी याचिका को संहिता में निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन प्राप्त जानकारी के रूप में है। हलफनामे को **19** के क्रम में निहित प्रावधानों पर मॉडल किया जाना है। कोड। इसलिए, सूचना के आधार या स्रोतों को कहा जाना आवश्यक है। "

(19) सिविल प्रक्रिया संहिता के क्रम **vi** नियम १५ में व्यक्त किए गए तरीके से याचिका का सत्यापन अनिवार्य रूप से होना है। उपरोक्त प्रावधान यहां निकाला जा रहा है:-

"15. याचिका का सत्यापन (**1)** के रूप में अन्यथा किसी भी कानून द्वारा प्रदान किए जाने के लिए प्रदान किया जाता है, प्रत्येक दलील को पार्टी द्वारा या किसी एक पक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संतुष्टि साबित करने वाले पक्षों द्वारा पैर पर सत्यापित किया जाएगा। कोर्ट के मामले के तथ्यों से परिचित होना।

(२) सत्यापित करने वाला व्यक्ति निर्दिष्ट करेगा, याचिका के गिने हुए पैराग्राफ के संदर्भ में, वह अपने स्वयं के ज्ञान का सत्यापन करता है और जो वह प्राप्त जानकारी प्राप्त करता है और उसे सत्य माना जाता है।

(३) वेरिफिशन को उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो इसे बनाने वाला होगा और उस तारीख को बताएगा जिस पर और उस स्थान पर हस्ताक्षर किए गए थे। "

(२०) प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा उन्नत प्रस्तुत करने के सटीक उद्देश्य को समझने के लिए, यह अनुच्छेद ६ (ए) में औसत तथ्यों के सत्यापन के बारे में बताने के लिए उपयुक्त माना जाता है:-

"... कि पैरा **6 (**ए) की सामग्री मेरे ज्ञान के लिए सही और सही माना जाता है और बिलु उर्फ दया नंद से प्राप्त जानकारी पर आधारित है **।**

(9) AIR 1974 SC 1957

(२१) प्रतिवादी की ओर से किए गए पूर्वोक्त औसत के जवाब में, यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि पैरा **6** (ए) की सामग्री को याचिकाकर्ता द्वारा अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर सत्यापित नहीं किया गया है "। पैरा **6** (ए) में किए गए औसत की सामग्री को बिलु **@** दया नंद एस **** ओ राम दयाल, आर/ओ मंडाय्या (कालक) जिला रेवारी से प्राप्त जानकारी के आधार पर सत्यापित किया गया है और साथ ही जानकारी के आधार पर भी। सुदेश सहगल, हरियाणा फोटो स्टूडियो। प्रतिवादी के लिए सीखे हुए वकील द्वारा उन्नत प्रस्तुत करने के लिए विरोध करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का ज्ञान ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों से लिया गया था और इसलिए, याचिकाकर्ता ने पैराग्राफ **6** में वर्णित तथ्यों के अपने ज्ञान के स्रोत को सत्यापित किया (ए)।

(२२) याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा संबोधित तर्क को संबोधित करना मेरे लिए संभव नहीं है। चुनाव याचिका के पैरा **6** (ए) में औसत के सत्यापन की एक करीबी परीक्षा से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है कि क्या उसने अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर या प्राप्त जानकारी के आधार पर तथ्यों को सत्यापित किया है। सत्यापन शेष याचिका के लिए भी समान रूप से दोषपूर्ण है। मेरे विचार में चुनावी याचिका में सत्यापन भी सिविल प्रक्रिया संहिता के **VI** नियम **15** को ऑर्डर करने के अनुरूप नहीं है।

(२३) जहां तक अंक नंबर ४ का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया है कि चुनाव याचिका से जुड़ा हलफनामा नागरिक प्रक्रिया संहिता और नियमों और उच्च न्यायालय के आदेशों के आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के लिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद **6** (ए) में सुनाई गई तथ्यों के संबंध में हलफनामे में इसका खुलासा नहीं किया गया है, उसमें किए गए औसत का हिस्सा याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही है और इसके आधार पर कौन सा हिस्सा सही है उसमें वर्णित व्यक्तियों से प्राप्त जानकारी। इस तथ्य के आधार पर कि हलफनामा

दोषपूर्ण है, यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल चुनाव याचिका इस स्तर पर ही अस्वीकार कर दी जाती है।

(२४) दोषपूर्ण हलफनामे के संबंध में अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए, प्रतिवादी के लिए सीखा वकील ने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बंबई राज्य बनाम पुरूषोत्तम जोग नाइक (10) में प्रस्तुत पर भरोसा किया है ।

"हम चाहते हैं, हालांकि, यह देखने के लिए कि यहां उत्पादित हलफनामे का सत्यापन दोषपूर्ण है। हलफनामे का शरीर बताता है कि कुछ मामलों को सचिव के लिए जाना जाता था जिन्होंने हलफनामे को व्यक्तिगत बनाया। सत्यापन हालांकि बताता है कि सब कुछ सबसे अच्छा था। उनकी जानकारी और विश्वास के रूप में। हम इसे इस प्रकार के स्लिपशोड सत्यापन के रूप में इंगित करते हैं कि किसी दिए गए मामले में हलफनामे की अस्वीकृति हो सकती है। क्या कोड में लागू होता है या नहीं।

रिलायंस को फिर से वीरेंद्र कुमार के मामले (सुप्रा) पर रखा गया था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा अंक नंबर 3 से निपटने के दौरान पहले से ही ऊपर निकाला जा चुका है।

गजानन कृष्णजी बापत और एक अन्य बनाम दत्तजी राघोबाजी मेघे और अन्य, (11) में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए, (11) ने प्रतिवादी के लिए वकील सीखा, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन के आधार पर अपने दावे को प्रमाणित करना है:--

"एक याचिका को भ्रष्ट अभ्यास के आरोप की आवश्यकता होती है, कानून द्वारा, एक हलफनामे द्वारा, चुनावी याचिकाकर्ता को भी भ्रष्ट अभ्यास के आयोग के संबंध में अपनी जानकारी के स्रोत का खुलासा करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह बांधने के लिए आवश्यक हो जाता है। चुनाव याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा लगाए गए आरोप और किसी भी मछली पकड़ने या रोने की जांच को रोकने के लिए और लौटे उम्मीदवार को आश्चर्यचकित होने से रोकने के लिए। "

प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा किए गए दावे का मुकाबला करते हुए, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने इस अदालत के नुकीले ध्यान को आमंत्रित किया है।

(10) AIR 1952 SCC 317

(11) (1995) 5 SCC 347

चुनाव नियमों में से, 1961 (इसके बाद '1961 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया। वही यहाँ निकाला गया है:-

[रूप]

साथ ही चुनावी याचिका में याचिकाकर्ता ने श्री/श्रीमती के चुनाव पर सवाल उठाया .. (प्रतिवादी नहीं ..... उक्त याचिका में) पूरी तरह से पुष्टि/शपथ और कहें-

(ए) कि पैराग्राफ में किए गए बयान ..... के साथ चुनाव याचिका के भ्रष्ट अभ्यास के आयोग के बारे में ..... और विवरण पैराग्राफ में उल्लिखित इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास ..... शेड्यूल के एनेक्स्ड थेरेटो मेरे ज्ञान के लिए सही हैं;

(d) कि पैराग्राफ में दिए गए बयान .... उक्त याचिका के भ्रष्ट अभ्यास के आयोग के बारे में ..... और इस तरह के भ्रष्ट अभ्यास के विवरण दिए गए पैराग्राफ में .... उक्त याचिका के और शेड्यूल के पैराग्राफ में एनेक्स्ड थेरेटो मेरी जानकारी के लिए सही हैं; .....

यह याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चुनाव याचिका में संलग्न हलफनामे ने 1961 के नियमों के लिए 25 के रूप में संलग्न किया। याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के तर्क का परीक्षण करने के लिए, चुनाव याचिका में संलग्न हलफनामे के पैराग्राफ 2 को यहां निकालना उचित माना जाता है:-

"यह कि पीपुल्स एक्ट, 1951 के प्रतिनिधित्व के 123 (1) के भ्रष्ट प्रथाओं के आयोग के बारे में याचिका के पैरा 6 (ए) में किया गया बयान, 1951

और एक ही याचिका के पैरा 6 (ए) में उल्लिखित इस तरह की भ्रष्ट प्रथाओं के विवरण मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही और सही हैं और बिलू उर्फ दया नंद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राम दयाल के निवासी गांव मंडया के पुत्र, जिला। रेवाड़ी और हरियाणा फोटो स्टूडियो, रेवाड़ी के सुधेश सहगल फोटोग्राफर से भी, जिसे माना जाता है कि यह सच है। "

अनुच्छेद 2 का एक अवलोकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील का विवाद रिकॉर्ड के बहुत चेहरे पर गलत है। पैरा 6 (ए) में उल्लिखित भ्रष्ट प्रथाओं को "..... ..... सही और सही मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के लिए सही और सही है ....." और "बिलु @ दया नंद बेटे से प्राप्त जानकारी के आधार पर भी चित्रित किया गया है। मंडाया के राम दयाल निवासी, जिला रेवाड़ी और हरियाणा फोटो स्टूडियो के फोटोग्राफर सुधेश सहगल से, रेवाड़ी ..... "यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर जो कुछ भी सत्यापित किया गया है, उसे भी सत्यापित किया गया है। जानकारी प्राप्त हुई। हलफनामा प्रतिवादी के लिए सीखा वकील द्वारा निर्भर निर्णय में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है। यह 1961 के नियमों से जुड़े 25 के अनुरूप नहीं है। पूर्वोक्त हलफनामे, इसलिए, पूरी तरह से दोषपूर्ण है।

(२५) पूर्वोक्त कमियों के बावजूद याचिकाकर्ता के लिए वकील सीखी गई वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि सत्यापन क्रम में नहीं है या हलफनामा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है, यह प्रतिवादी की याचिका को स्वीकार करना संभव नहीं है कि तत्काल चुनाव याचिका होनी चाहिए इस स्तर पर ही खारिज कर दिया जाए। इस ओर से, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने श्री एच। डी। में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान किए गए फैसले पर निर्भरता रखी है। रेवना का मामला (सुप्रा) जिसमें अनुच्छेद 14 में, यह माना गया है कि एक चुनाव याचिका के सत्यापन में दोष और संलग्न हलफनामे घातक नहीं बल्कि इलाज योग्य हैं। इसलिए, इस मामले की समग्रता में मेरे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि

चुनाव याचिका और हलफनामे से जुड़े शपथ पत्र का सत्यापन नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रतिवादी के दावे में कोई पदार्थ नहीं लगता है कि याचिका इस अवस्था पर एकमुश्त बर्खास्तगी के योग्य है ।

विजय सोमनी वी. कैप्टन अजय सिंह531

(जे.एस. खीर, जे।)

मुद्दा नंबर 5:

(२६) अंतिम रूप से, यह तर्क दिया गया है कि चुनाव याचिका की एक सच्ची प्रति प्रतिवादी से सुसज्जित नहीं की गई है। इस ओर से, प्रतिवादी के लिए सीखा वकील का विवाद इस तथ्य पर आधारित है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर देने वाले उत्तरदाता को भेजे गए हलफनामे की प्रति यह नहीं दिखाती है कि यह एक उपयुक्त व्यक्ति द्वारा उचित तरीके से सत्यापित किया गया है। यह बताते हुए कि उपरोक्त दोष चुनाव याचिका के लिए घातक है, सीखा वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ। शिपरा (श्रीमती) और अन्य बनाम शंती लाल खोईवाल और अन्य (12) में दिए गए फैसले पर निर्भरता रखी है। एपेक्स कोर्ट के पूर्वोक्त फैसले में जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया था, वह अनुच्छेद 8 में प्रस्तुत किया गया था और निम्नलिखित टिप्पणियों से पता लगाने योग्य है:-

"... जब एक याचिकाकर्ता को एक चुनावी याचिका दायर करने के लिए संलग्न किया जाता है, तो आवेदक द्वारा विधिवत शपथ ग्रहण के साथ शपथ ग्रहण किया जाता है, जो कि लौटाए गए उम्मीदवार को लगाए गए भ्रष्ट प्रथाओं के विविध आरोपों की विधिवत रूप से सत्यापित करता है और निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है। यह उसी तरह से किया जाएगा, जैसा कि नियम 94-ए के साथ नियमों में से एक के रूप में पढ़ा जाएगा। क्या उसमें निहित सत्यापन भाग के बिना प्रतिवादी को आपूर्ति की गई हलफनामे की प्रति (हालांकि मूल हलफनामे में निहित) को 'सही प्रतिलिपि "माना जा सकता है?

पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से दिया गया था-

"क़ाज़ी, जे। पुरूशोटम बनाम रिटर्निंग ऑफिसर ने, इस अदालत के उपरोक्त निर्णय के साथ -साथ अन्य निर्णयों और 1990 के चुनाव याचिका नंबर 2 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक अप्रतिबंधित निर्णय का उल्लेख करने के बाद, उन्होंने कहा कि चुनाव याचिका के साथ हलफनामे की कॉपी पर नोटरी का समर्थन की अनुपस्थिति

(12) (1996) 5 एससीसी 181

अधिनियम की धारा 81 (3) के अनुरूप नहीं है, और चुनाव याचिका को उक्त चूक के लिए खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

मेरी राय में, उपरोक्त निर्णय कानून को सही ढंग से छोड़ देता है और यहां चौकोर रूप से लागू होता है। विशेष रूप से, 1990 के चुनावी याचिका संख्या 2 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अप्रतिबंधित निर्णय में निम्नलिखित अवलोकन, क़ाज़ी के फैसले के पैरा 12 में उद्धृत किए गए, जे। शिक्षाप्रद हैं और उक्त निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं। अवलोकन निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैं:

", हालांकि, एक प्रश्न पर विचार करने के लिए छोड़ देता है और

यह है कि क्या समर्थन की प्रतिलिपि 'की पुष्टि की और नोटरी द्वारा मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए, का पदनाम नोटरी और स्टैम्पेड एंडोर्समेंट के बारे में पुष्टि करने के समय उन्होंने जो बनाया है, उसकी पुष्टि हलफनामा, आवश्यक और आवश्यक भाग थे दस्तावेज़ और यदि इन्हें प्रतिलिपि से छोड़ा गया है सुसज्जित, यह कॉपी को प्रस्तुत करेगा, जो है सुसज्जित, अधूरा, और दोष इतना चमकदार होगा नकारात्मक होने के कारण कि प्रतिलिपि थी सुसज्जित। जब फॉर्म नंबर 25 किसी विशेष को निर्धारित करता है फॉर्म और उस हलफनामे की प्रति सुसज्जित की जानी है, यह मुझे लगता है कि प्राधिकरण का समर्थन इससे पहले कि पुष्टि की गई थी, साथ में

उनका आधिकारिक पदनाम और मुद्रांकित समर्थन, भी आवश्यक हैं और उनके बिना कॉपी नहीं हो सकती है सच्ची प्रतिलिपि के रूप में माना जाता है। यह केवल सामग्री नहीं है हलफनामे में जो दस्तावेज़ में पवित्रता लाता है लेकिन जो पुष्टि की गई है, और उसके बिना पुष्टि, यह कोई हलफनामा नहीं हो सकता है। मैं नहीं हूँ श्री बोबडे को प्रस्तुत करने से प्रभावित है कि ये एंडोर्समेंट केवल औपचारिक थे, क्योंकि क्या है सेक्शन के उप-धारा (1) के लिए प्रोविजो के तहत आवश्यक है 83 एक हलफनामा है, और इसके लिए संभव होना चाहिए यह पता लगाने के लिए कि क्या वास्तव में, सामग्री है मजिस्ट्रेट के सामने शपथ ली, पुष्टि की और हस्ताक्षर किए गए या नोटरी या वह व्यक्ति जिसकी उपस्थिति में प्रतिज्ञान की कसम खाई गई थी, या शपथ दिलाने के लिए अधिकार था। प्रतिवादी उस व्यक्ति को यह इंगित करने की स्थिति में नहीं होगा

जिसे शपथ लेने के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति, अस्तित्व में नहीं था या शपथ को प्रशासित करने का कोई अधिकार नहीं था या यह कि कथित प्राधिकारी द्वारा किए गए दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर और समर्थन नकली थे । यदि हलफनामे की प्रतियां वफादार नहीं हैं और इन समर्थन को शामिल नहीं करते हैं, तो प्रतिवादी का एक मूल्यवान अधिकार दूर ले जाया जाता है और इस उद्देश्य पर विचार करते हुए कि एंडोर्समेंट की प्रतिलिपि सेवा करेगी, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह भाग अभिन्न अंग नहीं होगा हलफनामे की। चूंकि ये विवरण हलफनामे का एक अभिन्न अंग बनाते हैं, इसलिए उस हिस्से के बिना एक प्रति प्रस्तुत करना एक पूरी प्रति प्रस्तुत नहीं करेगी, और उस घटना में, केवल इसलिए कि लौटे उम्मीदवार ने एक समर्थन किया कि यह एक सच्ची प्रति थी, इसे नहीं माना जा सकता है। एक सच्ची प्रति। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसे सेवा दी जानी है, मुझे नहीं लगता कि चूक को असंगत माना जा सकता है "

> "सम्मान के साथ, मैं उक्त टिप्पणियों को अपने रूप में अपनाऊंगा। अपील को खारिज करने की आवश्यकता है।"
>
> यह उत्तरदाता के लिए सीखा वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त निर्णय को शीर्ष अदालत द्वारा टी.एम. जैकब वी। सी। पोलोस एंड ऑर्स। (13)। डॉ। शिप्रा के मामले (सुप्रा) में दृढ़ संकल्प के आधार पर, प्रतिवादी के लिए सीखा वकील ने कहा कि तत्काल चुनाव याचिका को किसी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और उसी को इस स्तर पर ही अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी है।

(27) चुनाव याचिका से जुड़ी हलफनामे की एक सच्ची प्रति की गैर-आपूर्ति के संबंध में प्रतिवादी के लिए सीखा वकील के विवाद के खिलाफ, याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील ने केवल यह बताया है कि निर्णयों पर भरोसा किया गया था। प्रतिवादी के लिए सीखा वकील तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए अनुचित हैं। याचिकाकर्ता की ओर से, रिलायंस को टी.एम. पर रखा गया है। जैकब का मामला (सुप्रा) जिस पर प्रतिवादी भी अपने दावे को प्रमाणित करना चाहता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद के निर्धारण के दौरान टी.एम. जैकब के मामले, डॉ। शिप्रा के मामले में प्रस्तुत निर्णय के विश्लेषण पर शीर्ष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रतिवादी को भ्रष्ट प्रथाओं की उनके प्रति आरोपों का समर्थन करने वाले हलफनामे की आपूर्ति

की गई जिस

---

(१३) JT. 1999 (3) SCC 72

ने यह व्यक्त नहीं किया कि यह एक नोटरी से पहले चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत शपथ और सत्यापित नहीं किया गया था। चुनाव याचिका में प्रतिवादी को आपूर्ति किए गए हलफनामे की प्रति में दूसरे शब्दों में, नोटरी एंडोर्समेंट की पूरी अनुपस्थिति थी। डॉ। शिपरा के मामले में सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हलफनामे की प्रति में पाया गया दोष इस प्रकार नोटरी या उसकी सील और स्टैम्प के नाम की अनुपस्थिति नहीं था, लेकिन "नोटरी एंडोर्समेंट" और इस तरह की पूर्ण अनुपस्थिति चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा "एक पुष्टि" या "शपथ" की अनुपस्थिति। यह पूर्वोक्त संदर्भ में था। जैकब के मामले (सुप्रा) कि डॉ। शिप्रा के मामले (सुप्रा) में पीठ ने पाया कि लौटे हुए उम्मीदवार को हलफनामे की "सच्ची प्रति" के एक अवलोकन पर छाप मिली होगी कि समर्थन में कोई विधिवत शपथ और सत्यापित शपथ पत्र दायर नहीं किया गया था। चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा भ्रष्ट प्रथाओं के आरोपों में से। टी.एम. जैकब के मामले (सुप्रा) प्रतिवादी को आपूर्ति किए गए हलफनामे की प्रति में दोषों को निर्णय के पैरा 41 में उजागर किया गया था, जिसे यहां निकाला जा रहा है:-

"हम पहले से ही दोष का उल्लेख कर चुके हैं जो वर्तमान मामले में अपीलार्थी पर सेवा की गई हलफनामे की प्रति में पाया गया है। इस बात का कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता पर सेवा की गई Affiadvit की प्रतिलिपि में वह प्रभाव था जो शपथ पत्र का प्रभाव था एक नोटरी से पहले चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए, सत्यापित और पुष्टि की गई। सत्यापन के समर्थन के नीचे, यह भी उल्लेख किया गया था:

एसडी/ नोटरी

हालांकि, अपीलार्थी पर सेवा की गई हलफनामे की प्रति में नोटरी के नाम और विवरण और नोटरी के स्टैम्प और सील का उल्लेख करने के लिए एक चूक थी। कोई अन्य दोष या तो आपत्ति के ज्ञापन में या सी.एम.पी. 1996 के नंबर 2903 या उच्च न्यायालय में या हमारे सामने तर्कों के दौरान भी। क्या इस चूक को एक महत्वपूर्ण या भौतिक प्रकृति के चूक के रूप में माना जा सकता है जो संभवतः अपने बचाव को तैयार करने में अपीलकर्ता को भ्रमित या पूर्वाग्रह कर सकता है? हमारी राय में सं। चूक असंगत थी। कल्पना के किसी भी खिंचाव से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को नाम और सील या हलफनामे की

प्रतिलिपि पर नोटरी का स्टैम्प की अनुपस्थिति से गुमराह किया जा सकता था।

जब प्रतिलिपि का समर्थन प्रतिलिपि में मौजूद था, जिसमें दिखाया गया था कि नोटरी द्वारा उसी पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि चुनाव याचिका की प्रतियां और अपीलकर्ता पर परोसे गए हलफनामे ने हर पृष्ठ पर प्रतिवादी नंबर 1 के हस्ताक्षर को बोर कर दिया और चुनावी याचिका के समर्थन में दायर मूल हलफनामा ठीक से हस्ताक्षरित, सत्यापित और पुष्टि की गई थी। चुनाव याचिकाकर्ता और नोटरी द्वारा सत्यापित। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 83 (1) (सी) के लिए प्रोविजो के साथ पढ़ी गई धारा 81 (3) की आवश्यकताओं के साथ पर्याप्त अनुपालन किया गया है। अधिनियम की धारा 81 के तहत सच्ची प्रतिलिपि की आपूर्ति में दोष को घातक माना जा सकता है, जहां पार्टी को मूल में भौतिक प्रकृति की भिन्नता और प्रतिवादी को आपूर्ति की गई प्रति के कारण कॉपी द्वारा गुमराह किया गया है। ऐसे मामलों में प्रतिवादी के कारण होने वाले पूर्वाग्रह से अधिनियम की धारा 86 (1) के साथ पढ़ी गई धारा 81 (3) के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा। समान परिणाम अधिनियम की धारा 83 के साथ गैर-अनुपालन से पालन नहीं करेगा। "

(28) तत्काल मुद्दे में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस अदालत को यह जांचना होगा कि क्या शपथ पत्र में दोष डॉ। शिपरा के मामले (सुप्रा) में व्यक्त प्रकृति का है या टी.एम. जैकब का मामला (सुप्रा)। दूसरे शब्दों में, डॉ। शिप्रा के मामले में हलफनामे की प्रति में नोटरी एंडोर्समेंट की पूर्ण अनुपस्थिति घातक होगी, जबकि एक संकेत है कि वास्तव में टी। जैकब का मामला घातक नहीं होगा।

(29) उत्तरदाता के लिए सीखा वकील ने लिखित बयान के साथ प्रतिवादी से सुसज्जित चुनाव याचिका की एक ज़ेरॉक्स कॉपी संलग्न की है। लिखित बयान से जुड़ी चुनावी याचिका की पूर्वोक्त ज़ेरॉक्स कॉपी की सत्यता या तो उसके द्वारा दायर प्रतिकृति में या याचिकाकर्ता की ओर से तर्कों के दौरान विवादित नहीं हुई है। ज़ेरॉक्स कॉपी के एक पर्सन से नोटरी द्वारा सत्यापन की कुल अनुपस्थिति का पता चलता है। ज़ेरॉक्स कॉपी से यह स्पष्ट है कि कोई संकेत नहीं है, जो भी, चुनाव याचिका की प्रतिलिपि पर प्रतिवादी से सुसज्जित है कि शपथ पत्र को चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ दिलाई गई थी या शपथ आयुक्त ने हलफनामे को देखा था। पूर्वोक्त तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में कानूनी स्थिति जो वर्तमान विवाद को नियंत्रित करेगा, वह है - डॉ शिपरा के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया मामला जिस मे

प्रतिवादी से सुसज्जित चुनाव याचिकाकर्ता के हलफनामे की कॉपी ने नोटरी की उपस्थिति में हलफनामे की पुष्टि को चित्रित नहीं किया। ऐसा होने के नाते, चुनावी याचिका में वर्तमान दोष 1951 अधिनियम की धारा 81 (3) के जनादेश के गैर-अनुपालन के लिए है, जिसके लिए आवश्यक है कि प्रतिवादी को चुनाव याचिका की एक ट्रूएन कॉपी सुसज्जित किया जाना चाहिए। 1951 अधिनियम की धारा 81 के तहत एक दोष 1951 अधिनियम की धारा 86 (1) के संदर्भ में एक लाइलाज दोष है। यहां तक कि डॉ। शिपरा के मामले (सुप्रा) के साथ -साथ टी.एम. जैकब का मामला (सुप्रा), पूर्वोक्त दोष लाइलाज है। मामले के पूर्वोक्त दृष्टिकोण में, मैं प्रतिवादी द्वारा उठाए गए 5 वें प्रारंभिक मुद्दे में प्रतिवादी के विवाद को बनाए रखता हूं। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रतिवादी को 1951 अधिनियम की धारा 81 (3) के संदर्भ में चुनावी याचिका की 'सच्ची प्रतिलिपि' से सुसज्जित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के लिए एक चुनावी याचिका को खारिज करना अनिवार्य है जो 1951 अधिनियम की धारा 86 (1) के जनादेश के तहत 1951 अधिनियम की धारा 81 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। त्वरित चुनाव याचिका, तदनुसार, खारिज करने के लिए उत्तरदायी है।

निष्कर्ष:-

(३०) ऊपर दर्ज किए गए निष्कर्षों के मद्देनजर, एनओएस १ और २ मुद्दों के संबंध में किए गए दावे इस आशय के लिए कि चुनावी याचिका में भौतिक तथ्यों की कमी है, कानून में स्वीकार्य नहीं हैं। हालांकि, चुनाव याचिका में भौतिक विवरणों में कमियां हैं, यह याचिका बरकरार है। चूंकि भौतिक पार्टिकुअर्स में केवल कमी है और भौतिक तथ्यों में नहीं, प्रतिवादी की दलील कि इस स्तर पर खारिज करने के लिए तत्काल याचिका को अस्वीकार कर दिया जाता है, को अस्वीकार कर दिया जाता है। यद्यपि यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चुनाव याचिकाकर्ता को लागत के रूप में शर्तों पर या अन्यथा के रूप में शर्तों पर संभोग विवरणों में अच्छी कमी को पूरा करने का अवसर दिया जा सकता है, यह तत्काल मामले में खींचे गए अंतिम निष्कर्ष को देखते हुए अनुचित माना जाता है। याचिकाकर्ता को भौतिक विवरणों में कमी को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(३१) इश्यू ३ और ४ के तहत प्रतिवादी द्वारा उठाए गए दलील के रूप में इस आशय के लिए कि चुनाव याचिका का सत्यापन और संलग्न हलफनामा क्रम में नहीं है, इसे बरकरार नहीं रखा गया है। हालाँकि, इस स्तर पर

सत्यापन और हलफनामे में दोषों के कारण चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना को स्वीकार करना संभव नहीं है। हालांकि इसका निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि चुनाव

याचिकाकर्ता को इस तरह के शर्तों पर सत्यापन और हलफनामे को ठीक करने का अवसर दिया जा सकता है, जैसे कि लागत या अन्यथा, इसे अंतिम निष्कर्ष के मद्देनजर अनुचित माना जाता है, जो कि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जानी चाहिए। सत्यापन और हलफनामे में कमी करें।

(32) अंक संख्या 5 में उठाई गई याचिका को आगे बढ़ाते हुए, यह माना जाता है कि प्रतिवादी को चुनाव याचिका की सच्ची कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

उपरोक्त दोष के दृष्टिगत प्रतिवादी की प्रार्थना कि चुनाव याचिका इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है को कायम रखा।

(३३) पूर्वोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर तत्काल चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया है।

जी.एस. सिंहवी और एम.एम. कुमार, जेजे

शम लाल शर्मा, पेटिटिटोनर बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, -वाद

C.W.P .. नंबर *7305* का *2002 22* नवंबर, *2001*

भारत का संविधान, *1950*-आर्ट्स। *39*-ए और *226*-कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, *1987*-चैप्टर *VI,* एसएस। *19* से *22*-याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा के बकाया राशि के देरी से भुगतान करने में ब्याज का दावा करते हुए एक रिट याचिका दायर की और रिटायरल बेनिफिट-केस को लोक एडलात-पक्षों को संदर्भित किया गया, जो एक निपटान/समझौता-लोक एडलत पर पहुंचने में विफल रहा, हालांकि, निर्णय लेते हुए, यह तय करना, योग्यता पर मामला-क्या लोके एडलैट्स नियमित अदालतों की भूमिका को ग्रहण कर सकते हैं और मामलों को तय कर सकते हैं कि डी हॉर्स समझौता या निपटान-कब्जा, लोके एडलैट के नो-ऑर्डर को अलग-अलग सेट करने के लिए-अधिकार क्षेत्र और लोक एडलैट्स के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को निपटाने के लिए। मामलों को महत्वाकांक्षी और गुंजाइश, कहा गया है।

आयोजित, कि निर्वाचन और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, *1987* के प्रासंगिक प्रावधानों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

जींद, हरियाणा